1	2	3
5.	हमीरपुर	89
6.	बांदा	323
7.	जालौन	65
8.	इटवा	--
9.	बिजनौर	--
10.	वाराणसी	21
11.	मिर्जापुर	216
12.	इलाहाबाद	437
13.	फतेहपुर	35
14.	जोनपुर	--
15.	आजमगढ़	--
16.	फैज़ाबाद	--
17.	बल्लिया	--
18.	गाजीपुर	--

Urban Land Ceiling Act

*417. SHRI P. M. SAYEED:
SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government propose to bring about major changes in the Urban Land Ceiling Act which are also expected to go a long way in releasing the hold of black money on urban property;

(b) if so, whether the Ministry has prepared a draft of the proposed amendments to the Urban Land Ceiling Act;

(c) if so, whether the Central Government propose to consult the State Governments before legislation is introduced;

(d) whether Union Government has received the comments on the proposed amendments from the various States; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI P. C. SETHI): (a) to (c). For some time past State Governments have been pointing out difficulties experienced in the administration of the Act as also lacunae in its provisions. There were also suggestions for amendment of the Act. With a view to identifying the areas where amendments are essential, the Government of India set up a Working Group in November, 1979. The Group has submitted its report which is under consideration in consultation with the State Governments.

(d) Not yet, Sir.

(e) Does not arise.

Memorandum received from Employees of Central Fisheries Corporation

*418. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have received any memorandum from the employees of Central Fisheries Corporation;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BIRENDRA SINGH RAO): (a) Yes, Sir.

(b) The Central Fisheries Corporation Employees Association in their Memoranda has been demanding mainly the revival of the Corporation on various grounds and suggesting measures to make the Corporation viable.

(c) The decision to wind up the Corporation is being considered by the Government in the light of the 49th Report of the Committee on Public Undertakings and the recommendations contained therein.

डाकघरों में गबन

*419. श्री राम लाल राही : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न डाकघरों में मनीआर्डर के झूठे भुगतान और लघु बचत खातों में

से धोखे से धन निकलवाने के कितने मामले प्रकाश में आए हैं और उनकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ;

(ख) क्या वाराणसी जिले में डाकघरों से लाखों रुपये के गबन के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी किस्म के मनीआर्डर और बचत बैंक के हानि और गबन के मामलों की संख्या प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है ।

विभाग द्वारा गबन को रोकने के लिए निम्न प्रयास किए गए :--

जांच और निरीक्षण नियमित रूप से किए जाने और पर्यवेक्षकीय नियंत्रणों को सुदृढ़ कर दिया गया है । दौरों और निरीक्षणों के दौरान निरीक्षण अधिकारियों द्वारा कुछ प्रतिशत मनीआर्डर भुगतानों और बचत बैंक निकासियों का सत्यापन किया जाता है ।

जाली भुगतानों एवं निकासियों के मामलों की विभागीय तौर पर पूरी तरह जांच की जाती है और उनकी रिपोर्ट पुलिस में की जाती है । दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध तुरन्त और कठोर कार्रवाई की जाती है ।

(ख) जी हां । तारीख 21-5-80 का एक पैम्फलेट जन, 80 में प्राप्त हुआ था जिसमें यह आरोप लगाए गए थे कि वाराणसी जिले में लाखों रुपये के जाली मनीआर्डर अदा किए गए ।

(ग) विभागीय जांच करने पर वाराणसी जिले में 14 जाली मनीआर्डरों के भुगतान का पता चला है । मामले की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गई और दो संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।

विवरण
तालिका

मनीआर्डर —

वर्ष	बुक किए गए मनीआर्डर		मनीआर्डर गबन के मामले	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1976-77	106633,000	9686526,000	612	571298
1977-78	107870,000	10473224,000	608	266774
1978-79	108287,000	11000025,000	509	349734
1979-80	अभी उपलब्ध नहीं है		553	286840

बचत बैंक

वर्ष	लेन देनों को संख्या	राशि	बचत बैंक गबन के मामले सं०	राशि
1976-77	146839620	16221200000	541	1247384
1977-78	154176665	19737[illegible]2000	512	1757319
1978-79	164622449	20326663000	693	2319148
1979-80	अभी उपलब्ध नहीं है ।		632	2169323

टिप्पणी : मनीआर्डर व बचत बैंक के गबन के मामलों की संख्या और राशि के आंकड़ों में जाली भुगतान/निकासी और साथ ही साथ मनीआर्डर बचत बैंक लेन देनों में हानि और गबन के अन्य प्रकार के मामले भी शामिल हैं ।